खण्ड: 2, अंक: 10 अक्टूबर 2019

# संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

## राजनीति एवं क्षेत्रीयता
## महाराष्ट्र व हरियाणा विधान सभा चुनाव, 2019

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2018

रूपाकंनः आर किशोर

# संश्लेषण

## राजनीति एवं क्षेत्रीयताः महाराष्ट्र एवं हरियाणा विधान सभा चुनाव, 2019

अनुक्रमिका


सम्पादकीय i-ii

1. महाराष्ट्र में अनैतिक गठबंधन की राजनीति 2019 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में

— जया ओझा 1—4

2. महाराष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तनीयताः विधान सभा चुनाव 2019

— सृष्टि 5—7

3. राज्यीय राजनीति के परिवर्तित आयामः महाराष्ट्र एवं हरियाण विधान सभा चुनाव 2019

— राखी 8—10

4. हरियाण एवं महाराष्ट्र के चुनाव परिणामः एक विश्लेषण

— पंकज 11—14

5. चुनावी लोकतंत्र एवं लैंगिकताः हरियाणा के विशेष संदर्भ में

— रजनी 15—17

# सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण को समसामयिक व विषयगत निरंतरता प्रदान करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। प्रत्येक माह के विचाराधीन विषय पर शोध वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों को शोधार्थियों द्वारा हिन्दो भाषा में प्रकटीकरण की हमारी यह पहल वर्ष 2018 से निरंतर कार्यरत हो रही है। शोध लेखन की केन्द्र की इस निरंतरता की अग्रणीयता में हम संश्लेषण के इस पंद्रहवें अंक को समस्त पाठकों के समक्ष प्रेषित कर रहें हैं।

वर्ष 2019 का अक्टूबर माह भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों की विधानसभा चुनावों से प्रभावित रहा। 17वीं लोक सभा चुनाव परिणाम पश्चात हरियाणा एवं महाराष्ट्र में होने वाले राज्य विधान सभाओं के इन चुनावों पर समस्त राजनीतिक दलों के अतिरिक्त मिडिया और मतदाताओं की भी अभिरुचि निरंतर बनी रही। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का इन दोनों ही राज्यों में बाहय मुख्यमंत्रियों का औचित्यपूर्ण समावेशन वैश्विक भारत की लोकतांत्रिक बाजार राजनीति में एक नवीन अनुभव था। जहाँ हरियाणा में श्री मनोहरलाल खटट्र के गैर–जाट् नेतृत्व द्वारा भाजपा शासन की वापसी का एक बार पुनः चुनावी परीक्षण था तो वहीं दूसरी ओर श्री देवेन्द्र फडनवीस का गैर–मराठा नेतृत्व के रुप में महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक चुनौतीपूर्ण निरीक्षण भी था। दोनों राज्यों में गठबंधन राजनीति की निरंतरता तथा विपक्षी केन्द्रिय एवं राज्यीय दलों, विशेषकर हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोक दल व नव गठित जननायक जनता पार्टी तथा महाराष्ट्र में शिव सेना व शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अस्तिव एवं अस्मिता का भी चुनावी परीक्षण था।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'राजनीति एवं क्षेत्रीयताः महाराष्ट्र व हरियाणा विधान सभा चुनाव, 2019' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पाँच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल इन दोनो राज्यों की लोकतांत्रिक व चुनावी राजनीति के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु 21वीं शताब्दी की गठबंधन राजनीति में राज्यीय दलों की परिवर्तनीय भूमिका का भी विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के पंद्रहवें अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ राज्यों की चुनावी राजनीति की परिवर्तनीयता तथा भारत के चुनावी लोकतंत्र में विधान सभा तथा लोक सभा के मध्य परस्पर मतदान रुझान में आये रुपांतरण को को भी प्रकट करते हैं। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता व सृजनात्मकता का परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार पल्लवित, प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। ।

संश्लेषण के पंद्रहवें अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के नवम्बर माह के अपने सोलहवें समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता व मौलिकता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

मंगलवार, 26 नवम्बर 2019

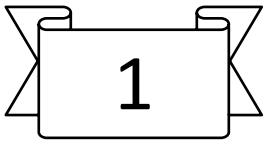


# महाराष्ट्र में अनैतिक गठबंधन की राजनीति 2019 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में

जया ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक दलों का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। हैरॉल्ड जे० लास्की अपनी पुस्तक "पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट इन इंग्लैंड" में यह तर्क देते हैं कि सरकार को नेताओं कि आवश्यकता होती है, जिसे संगठित लोगों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। संगठित दल, लोकप्रिय जनादेश प्राप्त करते हैं, जब उन्हें लोगों द्वारा समर्थन प्राप्त हो जाता है तब वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का कार्य करते हैं। भारत कि राजनीति शुरुआती दशकों से ही एक अनोखी राजनीति रही, जिसमें राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदलने में राजनीतिक दलों द्वारा उत्कृष्ठ भूमिका निभाई गई, राष्ट्रीय स्तर पर "कांग्रेस व्यवस्था" (रजनी कोठारी, 1964) से लेकर गैर–कांग्रेस व्यवस्था या गठबंधन की राजनीति में परिवर्तन दलों द्वारा ही संभव हुआ है। यह परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु राज्यीय स्तरों पर भी देखने को मिलता है। शुरुआती कुछ दशकों तक भारत में एक दलीय प्रधानता राष्ट्रीय व राज्यीय दोनों स्तर पर रही परंतु 1967 में राष्ट्र के अनेक राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी तथा नब्बे के दशक मेंराजनीतिक गठबंधन की सरकार वास्तविकता बन गई (श्रीधरन, 2004)।

इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय लोकतन्त्र संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जंहा पर भारतीय राजनीति 'गठबंधन की राजनीति' में परिवर्तित हो रही है। पिछले कुछ दशकों से प्रत्येक चुनावों में बहुमत ना मिलने के कारण विभिन्न दलों की मिली–जुली सरकार केंद्र व राज्यों में निर्मित हो रही है, जिसे गठबंधन की सरकार, संयुक्त सरकार या संविदा सरकार जसे कई नामों से जाना जाता है।

गठबंधन की राजनीति महाराष्ट्र के लिए भी कोई विचित्र विषय नहीं था। 1978 में शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र में पुरोगामी लोकशाही दल, जनता पार्टी, भाजपा–शिवसेना गठबंधन आदि गठबंधनों की राजनीति को भारत लंबे समय से देखता चला आ रहा है। आधुनिक भारत में महाराष्ट्र सामाजिक व आर्थिक रूप में अत्यधिक विकसित राज्य है। 1960 में महाराष्ट्र अस्तित्व में आया तब से लेकर 2014 तक यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई।

परंतु महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिदृश्य 2019 के विधान सभा चुनाव में दखने को मिला वह शायद ही महाराष्ट्र के इतिहास में देखा गया होगा। कभी–कभी सुदृढ़ सत्तारूढ़ दल को शासन से पदुच्यित करने के लिए गठबंधनों को बनाना स्वाभाविक माना जाने लगता है। प्रायः राजनीतिक गठबंधन चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात होते हैं, परंतु दो राजनीतिक दलों के गठबंधन की राजनीति का दृश्य जो महाराष्ट्र के विधान सभा चुनाव 2019 में सत्ता प्राप्ति के लिए दिखा वह आश्चर्यपूर्ण रहा।

भाजपा–सेना गठबंधन–

गठबंधन का एक दल 'शिवसेना' द्वारा चुनाव से पहले भाजपा के साथ मंच को साझा किया गया, जिसमें यह तय किया गया था कि देवेंद्र फंडनवीस पुनः मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे। भाजपा–सेना ने मिलकर चुनाव लड़ा एवं बहुमत प्राप्त किया परंतु चुनाव परिणाम आने के साथ ही शिवसेना ने अपने रंग बदल लिए। लोकसभा चुनाव से पहले किए गए किसी वचन को याद दिलाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा ढ़ाई वर्ष के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की जाने लगी, परंतु यह मांग भाजपा दल को स्वीकार्य नहीं थी।

परिणामस्वरूप शिवसेना दल ने अपने ही गठबंधन साथी को झूठा प्रमाणित करने के प्रयास में जुट गए। इस समय महाराष्ट्र की राजनीतिक समीकरण में कई तरीके के बदलाव दिखने लगे , सत्ता प्राप्ति की होड़ में वहां के दलों द्वारा कई राजनीतिक दांव पेंच खेले गए। किसी भी दल के पास पूर्णबहुमत न होने के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी गई, एवं राज्यपाल द्वारा भाजपा के नेता को बहुमत साबित कर सरकार निर्माण करने का आमंत्रण दिया गया, परंतु भाजपा बहुमत सिद्ध करने में विफल रही।

इसी समय एक एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, जिसमें भाजपा नेता देवेंद्र फंडनवीस द्वारा एन० सी० पी० (नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) नेता अजीत पवार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने का निश्चय कर लिया गया। परंतु बहुमत न सिद्ध करने के कारण यह गठबंधन भी टूट गया।

शिवसेना, एन० सी० पी० एवं कांग्रेस गठबंधन–

भाजपा द्वारा बहुमत सिद्ध न कर पाना शिवसेना के लिए एक अवसर की तरह देखा जा सकता है। अंततः शिवसेना ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा किया जिनके विरुद्ध विधान सभा का चुनाव लड़ा था। इस प्रकार शिवसेना ने एन० सी० पी० व कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करती है या इस खिचड़ी स्वरूपी गठबंधन में नए मतभेद को जन्म देगी।

परंतु महाराष्ट्र के चले इस प्रकरण में हर वह मतदाता स्वयं को ठगा अनुभव कर रहा होगा, जिसने अपना बहुमूल्य मत भाजपा–सेना गठबंधन को दिया था। योगेंद्र यादव इसे जनादेश कि चोरी बताते हुए कहते हैं कि भाजपा–एन० सी० पी० की सरकार अनैतिक व असंवैधानिक थी, जबकि शिवसेना, एन सी पी एवं कांग्रेस को सरकार बनाने का कानूनी अधिकार तो है परंतु यह नैतिक नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता द्वारा भाजपा–सेना गठबंधन को मत दिया गया था परंतु वहां किसी दूसरी गठबंधन की सरकार बनाए जाने से नैतिक संवेदनाए कुंद हो जाती है।

यद्यपि राजनीति में नैतिकता को ज्यादा महत्ता नहीं दी जातो है जैसा कि हंस जे० मार्गेथ्यु ने कहा है राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। परंतु भारतीय राजनीति में कहीं न कहीं नैतिकताओं का भी महत्व रहता है, जो लोगों को राजनीति से जोड़े रखता है। महाराष्ट्र में आम जन की भावनाओं से परे जा कर शिवसेना द्वारा यह निर्णय लिया जाना नैतिकता के विरुद्ध था जिसे "अनैतिक गठबंधन' कहा जा सकता है।

चुनाव परिणाम आने के बाद सहसा बदले शिवसेना के विचार ने न केवल महाराष्ट्र, अपितु देश के एक बड़े वर्ग को आश्चर्यजनक की स्थिति में डाल दिया, इससे गठबंधन की राजनीति पर प्रश्नचिन्ह लग गई है। इस राजनीति में उसी तरह सुधार की आवश्यकता की जाने लगी है जैसे कभी दल–बदल राजनीति में की गई थी। चुनावपूर्व हुए गठबंधनों की आपसी सहमति का होना अत्यंत ही अनिवार्य है, इसके साथ ही इनके मध्य हुए वचनबद्धताओं को सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है ताकि आरोप प्रत्यारोप का अवसर ही न मिले। अतः लोकतन्त्र में दो या दो से

अधिक दलों के बीच होनेवाला कोई भी चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात समझौता अंततः 'लोक' के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इससे लोकतन्त्र की बुनियादी धारणा एवं इसकी सुदृढ़ता बनी रहेगी।

♦♦♦♦♦

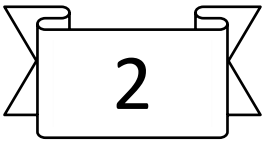


# महाराष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तनीयताः विधान सभा चुनाव 2019

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पिछले दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आए, तब भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक कार्यकर्ताओं को आघात पहुँचा कि जनता क्या चाहती है? कुछ ही माह पूर्व लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी इस सफलता से भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों का बढ़ जाना अस्वाभाविक नहीं था, अपितु महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम जनता की भिन्न इच्छाओं को अभिव्यक्त कर रहे थे। केंद्र व राज्य के लिए उनका चयन भिन्न–भिन्न है। 2014 में भी लोक सभा चुनाव के कुछ ही समय पश्चात दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपनी क्षेत्रीय मुद्दों की प्राथमिकताओं के आधार पर अपने मत का प्रयोग किया था। 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व हुए विधानसभा चुनावों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में जनता ने जिस स्वरूप में प्रदर्शन किया था, उसके विपरीत लोकसभा चुनाव में किया। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर बीते एक माह से चले आ रहे विवाद का अंत हुआ और अंततः शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के18वें मुख्यमंत्री शपथ दिलाई गयी। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के रूप में पदारूढ़ होने के साथ अनेक बाते जुड़ी हुई है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हुई है। और इनका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है।

हालांकि शिवसेना ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके सरकार का गठन किया था और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया। तथा चुनाव परिणामों में उनका दल सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। परंतु विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने हेतु आवश्यक संख्या उनके पास नहीं थी। अपितु देवेंद्र फड़णवीस भी यह अनुमान लगाने में असफल रहे। विशेषकर उस स्थिति में भी जब ढाई–ढाई वर्ष के सत्ता के बंटवारे की शिवसेना ने मांग रखी। यदि इस मांग को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लेती तो यह भारतीय राजनीति में एक और गलत परंपरा बनती। लगभग दो–गुनी

से अधिक सीटें जीतने वाला दल सत्ता में सहयोगी की भूमिका में रहे और छोटा दल सत्ता का नेतृत्व करे, यह उस जनता का अपमान होता, जिसने सबसे बड़े दल का चयन किया है। वैसे भी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, उसे चाहे जितना भी संविधान की रक्षा के रूप में प्रचारित किया जाए, यह राज्य की जनता के बड़े भागों के मतों का अपमान ही है, क्योंकि जनता ने चुनाव पूर्व गठबंधन को जीत दी थी। प्रधानमंत्री जी स्वयं महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र का नारा दे आए थे। प्रधानमंत्री जी  का मानना था कि यदि ढाई–ढाई वर्ष के सत्ता की विभाजित मांग को स्वीकार किया गया तो शिवसेना इसे अपनी जीत के स्वरूप में प्रचारित करेगी और इसके संकेत उचित नही जाएंगे। इसलिए भाजपा ने महाराष्ट्र की सरकार का परित्याग करना अधिक उचित समझा।

यह पहली बार है कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व कर रहा है। शिवसेना ने अपने प्रतिद्वंद्वी, किन्तु अब सहयोगी दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी) व काँग्रेस के साथ गठबंधन कर तीन दशक तक चुनाव में सहयोगी रही भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ते हुए, उसे विपक्ष में बैठने को विवश कर दिया। पहली बार है कि महाराष्ट्र में काँग्रेस ने ऐसे दल के साथ हाथ मिलाया है, जो सदैव से ही सिद्धांतः उसका विरोधी रहा है। शिवसेना के समर्थकों का मानना है कि उनका दल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शक्तिशाली नेतृत्व की आक्रामकता और विस्तारवाद से त्रस्त हो गया था।

उनका मानना था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा का नेतृत्व शिवसेना को तुच्छ लाभ के लिए बाहर कर देना चाहता था। अपने बहुत पुराने दल को सहन नहीं कर पा रहा था, और शिवसेना के अस्तित्व पर बन आई थी। जिस प्रकार गुपचुप सुबह–सुबह देवेंद्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई गयी और उसके बाद एनसीपी में दलबदल करने का प्रयास किया गया। इससे भाजपा और फड़णवीस की छवि अत्यधिक आक्रमक दिखने लगी। और लग रहा था कि भाजपा और उसके नेता सत्ता के भूखे है। इस क्रम में भाजपा ने उस नैतिक लाभ को भी गंवा दिया जो उसने शिवसेना के भाजपा से अलग होने संबंधी निर्णय से प्राप्त किया था। गठबंधन तोड़ने का ठीकरा, शिवसेना के सिर फूटा था, अपितु उसके पश्चात के घटनाक्रम में भाजपा ने नैतिक रूप से सब कुछ खो दिया। ठाकरे नम्र, मध्य वर्गीय जन की छवि रखने वाले पचास वर्ष की आयु कर चुके मराठी मानुष है। वह संगठन के व्यक्ति माने जाते है, जिन्होंने कठिन समय में शिवसेना का

कुशलता से नेतृत्व किया। बाबा साहब ठाकरे की मृत्यु के पश्चात आर दल में विभाजन के समय उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी सरकार का राज्य स्तर पर नेतृत्व नहीं किया।

इसके अतिरिक्त ठाकरे के लिए आगे की राह भी आसान नहीं होगी। क्योंकि इस बात को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि शिवसेना, एनसीपी और काँग्रेस सरकार का गठन ऐसे तीन दलों ने मिलकर किया है, जो सिद्धांतः भिन्न रही है। इन दलों में किस स्तर तक भिन्नता है, वो उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी दिखाई पड़ी। अधिक विचार–विमर्श के पश्चात तीन सप्ताह के पूर्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया था। न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रस्तावना में कहा गया था कि गठबंधन की सह–भागीदार दल संविधान में प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबंध है।

शिवसेना के लिए एक विकासोन्मुख दल के रूप में उभरना आसान काम नहीं होगा। उसके लिए हिंदुत्ववादी राजनीति से दूर होना अत्यंत कठिन काम होगा। शिवसेना धरती–पुत्र के नाम पर आंदोलन चलाने वालों में प्रारम्भिक दलों में सम्मिलित रही है। इस मानसिकता से बाहर आकर समावेशी समाज के विचार को आत्मसात करना शिवसेना के लिए बड़ी बात होगी। कुछ मुद्दों को लेकर गठबंधन के सहयोगी दल आमने–सामने आ सकते है। चूंकि उद्धव के पास राजनीतिक व प्रशासनिक अनुभव कम है, इसलिए उन्हें शरद पवार पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे अहं का टकराव व दानों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव जैसी बाते हो सकती है। काँग्रेस के लिए सबसे चुनौती यह रहेगी कि भाजपा के पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ अपने गठबंधन का औचित्य कैसे सिद्ध करती है।

भाजपा को सत्ता से दूर रखने की इच्छा व सत्ता में बने रहने की चाहत इन दलों को बंधे रखने का साधन होगी। अपितु इससे भी अधिक इन दलों को बंधे रखने का एक मुख्य तत्व होगा इनके अस्तित्व का प्रश्न। अतः अब बहुत कुछ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निर्भर करता है कि इन तीनों दलों का गठबंधन कैसे भूमिका निभाता है। अतः उनके संगठन व सरकारी मशीनरी की सहिष्णुता, कूटनय एंव कुशलता पर निर्भर करता है।

♦♦♦♦♦

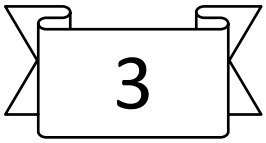

3

# राज्यीय राजनीति के परिवर्तित आयामः महाराष्ट्र एवं हरियाण विधान सभा चुनाव 2019

राखी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

महाराष्ट्र तथा हरियाणा राज्यों के चुनाव इस वर्ष लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों पश्चात भारतीय राजनीति के संदर्भ में हुआ दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। महाराष्ट्र के चुनावी राजनीति में वर्षों पुराना बीजेपी तथा शिवसेना का गठबंधन समाप्त हो गया जबकि हरियाणा में इस दल के साथ कुछ महीनों पूर्व गठित हुए दल ने कांग्रेस के विरुध गठबंधन में अपनी शुरुआत उपमुख्यमंत्री के पद से की है। चुनाव में विरोधी दलों द्वारा मोदी सरकार के लोकतंत्र की हत्या के आरोप के पश्चात भी इन दो राज्यों में भारतीय जनता दल तथा इसके सहयोगी दलों के मत प्रतिशत की समीकरण मुख्यतः केंद्रीय स्तर पर सरकार के निर्णयों से प्रभावित हुई है चाहे वह मुद्दा अनुच्छेद 370 का हो, राम मंदिर का अथवा तीन तलाक। यह सभी निर्णय विभिन्न राज्यों में जनता द्वारा भारतीय जनता दल के सहयोग तथा विरोध का आधार बने हैं। जबकि कांग्रेस तथा अन्य विरोधी दल स्थानीय नेताओं की व्यक्तिगत पहचान को आधार बनाकर चुनाव में शामिल हुए किन्तु केन्द्रीय स्तर पर उठाये जा रहे मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया के अलावा प्रभावी हितो के प्रति क्रियाशीलता की कमी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु राज्य राजनीति में भी इनकी छवि को प्रभावित किया है।

बीजेपी द्वारा हरियाणा विधानसभा सीटों के लिए नारा रखा गया 'अब की बार 75 पार' तथा अपने एजेंडे के तहत महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यतः दो तिहाई बहुमत बीजेपी तथा शिवसेना के गठबंधन को दिलाने तथा साथ ही बीजेपी को बहुमत दिलाने का लक्ष्य निश्चित किया गया। हालांकि 24 अक्टूबर को आए चुनाव नतीजों ने यह रणनीतियां पूर्णता सफल नहीं दिखी। महाराष्ट्र में 286 में से105 तथा हरियाणा में 90 में से केवल 40 सीटों पर ही सफलता प्राप्त हुई। हालाँकि इन सभी समीकरणों के पश्चात भी बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा के अनुपात को कायम नहीं रख सका। महाराष्ट्र से अधिक बीजेपी को उत्तरी भारत के हरियाणा के प्रदर्शन

हेतु अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है जहां कांग्रेस केवल 9 सीटों से ही केवल पीछे रही । इसके अलावा जेजेपी तथा एनसीपी को भी इन राज्यो में राजनीतिक रूप से अपने स्थान को कायम रखने हेतु अधिक प्रयासरत रहना होगा क्योंकि जहा जेजेपी के रूप में एक नव गठित दल को जनता ने इसके स्थानीय जनहित मुद्दों के आधार पर मत दिया है वहीं शरद पवार के सेवा निव्रत्ती के समय के नजदीक होने के पश्चात भी इन्हें जनता ने समर्थन देकर एक विकल्प दिया है । परंतु यह दोनों ही दल इन राज्यो की सरकार के निर्माण में नील का पत्थर साबित हुए है जिनके बिना सरकार बनाना न तो बीजेपी के लिए मुमकिन था न कांग्रेस के लिए । हरियाणा में जेजेपी ने भ्रष्टाचार तथा रोजगार के मुद्दों पर जनजीवन के सहयोग को प्राप्त किया वही महाराष्ट्र में शिवसेना ने स्थानीय वर्ग के मार्गदर्शक के रुप में अपनी पहचान बनाई हुई है।

बीजेपी के आधार के रूप में यह दो राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह दोनों ही दल मुख्यतः मजबूत जनाधार हैं जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में एनडीए सरकार के मत प्रतिशत में अहम आंकड़ों का योगदान दिया है इसके अलावा महाराष्ट्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार होने के कारण देश की राजनीति को तय करने में भौगोलिक रूप से अहम है लोकसभा की सदस्य संख्या भी इस राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के पद हेतु जिन व्यक्तियों का चुनाव किया गया है वह इन राज्यों की जनता के लिए गैर पारंपरिक प्रदान नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं जहां हरियाणा में जाटों के वर्चस्व पर मनोहर लाल खट्टर एक पंजाबी समुदाय से है वही देवेंद्र फडणवीस मराठा बहुलक राज्य में एक ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते है जो अपने आप में अलग अनुभव है।

दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने गठजोड़ के तहत सरकार बनाने हेतु गैर कांग्रेसी दलों का साथ प्राप्त करते हुए सत्ता में बने रहने की अपनी रणनीति को कायम रखा है हालांकि हरियाणा के विपरीत महाराष्ट्र में यह समीकरण शिवसेना के मुख्यमंत्री पद की मांग हेत, कायम नही रह सकी जिससे इस राज्य में इन दोनों ही दलों का एक अलग रवैया दिखा किंतु इसके पश्चात भी राज्य में बीजेपी ने एक अलग तथा महत्वपूर्ण जगह राजनीति में बनाए रखने हेतु अपनी रणनीतिया कायम रखी है। हरियाणा में इसके विपरीत बीजेपी का जेजेपी के साथ सरकार बनाना इसलिए भी अहम् है क्योंकि हरियाणा के इतिहास में 53 वर्षों में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी मंत्री उप–मुख्यमंत्री के कार्यकाल हेतु चयनित हुआ है। परिणाम स्वरूप यह कहना उचित नहीं है कि बीजेपी एक सुव्यवस्थित संगठित रचना के आधार पर विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई इसका कारण कांग्रेस दल का आंतरिक संगठन संरचना में कमी को पुरजोर तरीके से लाभ इन

दोनों राज्यों की राजनीति में बीजेपी को हुआ है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे ने इस दल के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पार्टी छोड़ने की शंका पर कुछ शक्तियां आवश्यक सौंपी गई किंतु वह केवल इस पार्टी के विभाजन का एक नया स्वरूप ही था क्योंकि इसके पश्चात भी चुनाव में इस पार्टी के प्रदर्शन में अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में इसके विपरीत कोई प्रभावकारी नेता न होने के कारण यह मोर्चा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी के विरुद्ध संभाला।

बुनियादी मुद्दे जैसे रोजगार शिक्षा पानी कृषि की गुणवत्ता में सुधार, आम जनजीवन के रहन सहन में सुधार आदि स्थानीय मुद्दे सदैव किसी भी राज्य की राजनीतिक दशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है किंतु इन दोनों ही राज्यों के चुनाव में जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वह राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की नीतियां रही जिसने संपूर्ण देश के प्रत्येक नागरिक के जनजीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है यह दोनों ही राज्य केंद्र में शासित भारतीय जनता दल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में भारतीय जनता दल के द्वारा दोबारा शासन में चयन के पश्चात् यह पहले राज्य है जिनमें पदग्रहण का कारक बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है दोनों ही राज्यों में बीजेपी के विरोध तथा सहयोग दलों का सत्ता में प्रवेश का कारण बन गया है। बीजेपी को महाराष्ट्र तथा हरियाणा में बहुमत अवश्य रहा किंतु उसका कारण राज्य में इन दलों का बेहतर से अधिक केंद्र में बीजेपी की राजनीति गतिविधिया है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे अहम् होते हैं किंतु इन दोनों ही राज्यों के चुनाव में स्थानीय मुद्दों से अधिक केंद्रीय नेतृत्व ने यहां की राजनीतिक समीकरण को निश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है।

♦♦♦♦♦

4

# हरियाण एवं महाराष्ट्र के चुनाव परिणामः एक विश्लेषण

पंकज

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

2019 लोकसभा चुनाव के पांच महीने पश्चात आये हरियाणा एंव महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव में नये परिणाम देखने को मिले। जिसने ये स्पष्ट कर दिया की भारतीय लोकतंत्र निरंतर परिवर्तनशील है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की कमजोर पक्षों को भी प्रदर्शित किया। वास्तव में चुनाव परिणाम बीजेपी जैसी राष्ट्रीय दल के लिए हार–जीत का विषय न होकर भविष्य के लिए सबक है। इसलिए बीजेपी को अपने दल को ओर अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न सत्रों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए बीजेपी को "क्षेत्रीय सूत्रीकरण के नियम" पर कार्य करना चाहिए। क्षेत्रीय सूत्रीकरण का नियम मुख्य तीन पक्षों पर आधारित है। प्रथम, क्षेत्रीय संगठन एवं नेतृत्व द्वितीय, क्षेत्रीय मुद्दे तृतीय, क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण।

## क्षेत्रीय संगठन एवं नेतृत्व

भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन एवं नेतृत्व समय के साथ जिस तरह से शक्तिशाली हो रहा है, उसके साथ राज्य स्तरीय संगठन एवं नेतृत्व में मजबूती देखने को नहीं मिलती है। वास्तव में स्थिति यह है कि राज्य स्तरीय संगठन एवं नेतृत्व पूर्ण तौर पर राष्ट्रीय संगठन एवं नेतृत्व पर निर्भर रहने लगा है। हरियाणा एवं महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम बीजेपी के कमजोर पक्ष की तरफ इशारा करते हैं। दोनों राज्यों के संगठन एवं नेतृत्व पर दृष्टि डाली जाए तो और विपक्षी दलों के संगठन एवं नेतृत्व से तुलना की जाए तो कमजोर परिलक्षित होता है। हरियाणा राज्य में संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है एवं इसमें जो नेतृत्व है उसकी जनता में सक्रिय छवि का अभाव है। इसके अलावा स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अन्य उच्च नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के द्वारा खड़ा किया गया है। हरियाणा बीजेपी के कुछ नेताओं जैसे अनिल विज कृष्णपाल गुर्जर आदि को छोड़ दे तो अन्य दलों से बीजेपी में आए हैं। जो संगठनात्मक मजबूती पर आधारित न होकर अवसरवादी प्रवृत्ति से संचालित होते हैं। लगभग यही स्थिति महाराष्ट्र में बीजेपी के संगठन की

ह। विशेषता गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के पश्चात किसी ऐसे नेतृत्व का अभाव है जो पूरे राज्य में अपनी स्वीकृत स्थापित कर सके। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा राज्य नेतृत्व में स्थापित किया गया है। इसके विपरीत विपक्षी दलों का दोनों राज्यों में राज्य स्तरीय नेतृत्व बहुत मजबूत है जैसे हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट प्रभावशाली क्षेत्र पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा किरण चौधरी कुलदीप बिश्नोई और कुमारी शैलजा का भी संगठन के साथ–साथ राज्य नेतृत्व में विशेष भूमिका है। हरियाणा के क्षेत्रीय दलों में जहां इंडियन नेशनल लोकदल के पतन के पश्चात उसके विकल्प के रूप में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी ने विशेष भूमिका राज्य स्तरीय राजनीति में प्रदान की है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार एवं अन्य राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रदान करता है। ऐसे सक्रिय राज्य स्तरीय नेतृत्व का अभाव भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

क्षेत्रीय मुद्दे

लोकसभा चुनाव के पश्चात से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है कि हरियाणा महाराष्ट के चुनाव को राष्ट्रीय विषय एवं मुद्दों के आधार पर जीता जाए। बीजेपी राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय मुद्दों को अपने चुनाव प्रचार में विशेष महत्व नहीं दिया। जबकि विपक्षी दल जनता तक क्षेत्रीय मुद्दों को पहुंचाने में सफल रहे हैं। हरियाणा एवं महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने राष्ट्रवाद, कश्मीर में धारा 370 हटाने को अपनी विशेष सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि इन्हें राष्ट्रीय विषयों का प्रभाव राज्य की जनता के ऊपर पड़ा है। परंतु यह विषय इस तरह से सफल नहीं हो पाए कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिला सकें।

इसके विपरीत विपक्षी दलों ने जनता का ध्यान क्षेत्रीय मुद्दों की ओर आकर्षित किया जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कृषि समस्याओं, बेरोजगारी के आंकड़ों के माध्यम से जनता को दिखाया कि हरियाणा में सत्तारूढ़ दल इस विषय का समाधान करने में असफल रही है। इसक साथ क्षेत्रीय विपक्षी दल जननायक जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा हरियाणा के युवाओं के लिए राज्य में युवाओं के रोजगार के लिए आरक्षण, कृषि ऋण माफी आदि लोकलुभावन नीति प्रस्तुत करके राज्य में के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने महाराष्ट्र में आए कृषि संकट की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया एवं इसके परिणाम भी निकल कर सामने

आए। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा आर पूर्ण बहुमत से बहुत दूर हो गई। वास्तव में बीजेपी की प्रचार नीति की महत्वपूर्ण भूली यही रही कि राष्ट्रीय मुद्दों को क्षेत्रीय व राज्यस्तरीय मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की गई और जनता के परिवर्तित स्वभाव को समझने में असफल रही। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के द्वारा क्षेत्रीय मुद्दे एवं पहचान को पुनः प्रभावित करने में सफल रहे।

क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण

तृतीय पक्ष जिसका अभाव भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति में हरियाणा एवं महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला वह हैं क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण को अनदेखा करना। 2019 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी के द्वारा राष्ट्रीय विषय विशेषकर राष्ट्रवाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक आदि विषय के नाम पर एक राष्ट्रीय जनमत अपने पक्ष में करने में सफल रही। द्वितीय भारतीय जनता ने लोकसभा चुनाव में सामाजिक विच्छेद (जाति, भाषा, क्षेत्र) आदि पक्षों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। हालांकि यह इस चुनाव में प्रासंगिक तो रहे, परंतु प्राथमिक नहीं रहे। इसके विपरीत हरियाणा एवं महाराष्ट्र के चुनाव में सामाजिक समीकरण में जाति एवं क्षेत्रीयता के पक्ष ने राष्ट्रीय विषयों से अधिक प्राथमिकता दी। बीजेपी के द्वारा अपनी दलीय कार्यनीति में राष्ट्रवाद राष्ट्रीय विषय एवं विशिष्ट व विस्तृत पहचान हिंदुत्व पर ज्यादा जोर दिया। जबकि क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण या सामाजिक गठजोड़ को वैकल्पिक नीति के रूप में रखा गया। जिसकी क्षति इन राज्य चुनाव के परिणाम के रूप में उठानी पड़ी।

दोनों राज्यों में व्यापक दृष्टि डालें तो बीजेपी की सामाजिक गठजोड़ की नीति हरियाणा में गैर– जाट एवं महाराष्ट्र में गैर– मराठा केंद्रित रही है। परंतु इन चुनाव में समाज स्तरीय नीति में कई कमियां रही है। हरियाणा में बीजेपी ने सामाजिक गठजोड़ की बजाय राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय प्रभावशाली नेतृत्व को अनदेखा करना एवं हिंदुत्व क मुद्दे पर केंद्रित रही जिसमें बीजेपी का मुख्य गैर– जाट मतदाता को अपनी तरफ व्यापक रूप से आकर्षित करने में असफल रही। जबकि हिंदुत्व की राजनीति हरियाणा जैसे राज्य में इसलिए कार्य नहीं कर पाई क्योंकि यहां मुस्लिम जनसंख्या बहुत कम है। यहां की चुनावी राजनीति धार्मिक– विभेद की बजाय जातीय समीकरण से संचालित होती है। बीजेपी के द्वारा गैर– जाट समीकरण को अनदेखा करने पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका पूरा लाभ उठाया गया। कांग्रेस नेतृत्व सामाजिक स्तर पर जाट– जाटव गठजोड़

करने में सफल रहा। जिसके कारण जाट प्रभावशाली क्षेत्र रोहतक, सोनीपत, भिवानी एवं दक्षिणी हरियाणा में विशेष सफलता प्राप्त की।

द्वितीय बीजेपी के लिए एक और महत्वपूर्ण समस्या गैर जाट वोटों में विभाजन की रही। क्योंकि बहुत से गैर जाट मतदाताओं के द्वारा राजकुमार सैनी की नेतृत्व वाली जाट विरोधी दल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को अपना समर्थन दिया गया। जिसके कारण बहुत सी सीटों पर बीजेपी के मतदाताओं में विभाजन हो जाने के कारण स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जहां बीजेपी के लिए खेल बिगाड़ने वाली, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस एवं जननायक जनता पार्टी के लिए चुनाव में इनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त करने में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तृतीय नया क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के कोर मतदाता ग्रामीण किसान जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने गैर– मराठा जातियों के लिए एक सक्रिय विकल्प एवं योजना प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण पूर्ण बहुमत और सत्ता दोनों से दूर रहना पड़ा। इसमें महत्व पक्ष यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक ब्राह्मण चेहरा प्रस्तुत किया गया। जो निम्न जाति समुदाय विशेषकर पिछड़े एवं दलितों को गैर– मराठा जातीय गठजोड़ में शामिल नहीं कर पाया।

व्यापक तौर पर दृष्टि डाली जाए तो इन चुनाव में एक मुख्य तथ्य यह निकलकर सामने आ रहा है कि इन दोनों राज्यों की जनता ने राष्ट्रीय एवं राज्य चुनाव में अंतर करना शुरू कर दिया है। इसका कारण यह भी है कि तेजी से सूचना आम जनमानस को प्राप्त होने लगी हैं। जिससे लोगों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय चुनावी राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल को अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। बल्कि क्षेत्रीय सूत्रीकरण क नियम को अपनाकर अपने आप को क्षेत्रीय संगठन एवं नेतृत्व, क्षेत्रीय मुद्दे एवं क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण से भी तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार बीजेपी को इन राज्यों के चुनाव परिणामों को हार– जीत के रूप में न लेकर सबक एवं सीख लेने के रूप में लेना चाहिए। ताकि भविष्य में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय चुनाव पक्षों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके।

♦♦♦♦♦

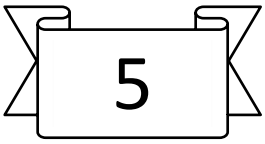

# 5

# चुनावी लोकतंत्र एवं लैंगिकताः हरियाणा के विशेष संदर्भ में

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के राज्य हरियाणा में, देश में सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है जहां पितृसत्तात्मक जड़ो ने अपनी नींव को मजबूती से जकड़ा हुआ है, जिस कारण यह अपने तिरछे लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) के लिए लोकप्रिय है, पंरतु यह जड़े कुछ समय से कमजोर होती दिखाई दे रही है जिसका ज्वलंत उदाहरण हरियाणा में होने वाले चुनाव है। हरियाणा में प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए 832 महिलाएं ही उपलब्ध हैं, लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एसोसिएशन ने सभी प्रतियोगी दलों के बीच लिंग भागीदारी में एक स्पष्ट अंतर को दर्शाया है, यहां तक कि राजनीतिक दल भी अपने अभियानों में महिला केंद्रित मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हरियाणा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागेदारी कम ही देखने को मिलती हैं। 'इंडिया टुडे डेटा इंटेलीजेंस यूनिट' के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि 2014 से 2019 में महिला प्रतियोगियों की संख्या 116 से घटकर 108 हो गई है। 2019 के चुनाव में कम महिलाओं को ही चुनाव लड़ते देखा गया। हालांकि हरियाणा में प्रमुख राजनीतिक दलां ने पहलवान बबीता फोगट और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगट जैसी प्रभावशाली महिला व्यक्तित्वों को मैदान में उतारा गया है, यह समग्र परिदृश्य को बहुत कम जोड़ता है। हरियाणा विधानसभा की कुल संख्या 90 है, जिसमें केवल पाँच पार्टियाँ 80 से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं।

2014 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 90 उम्मीदवारों में से कुल 12 उम्मीदवार महिला हैं। 2014 में इसने 15 महिलाओं को मैदान में उतारा था। राज्य में इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी, कांग्रेस ने पिछली बार 10 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, उन्होंने इस बार भी अपना नंबर बरकरार रखा है। वहीं नए प्रवेशी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी), जो पिछले

साल आईएनएलडी से अलग हुई थी, के द्वारा 88 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, जिनमें से केवल सात महिलाएं हैं। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) द्वारा 82 उम्मीदवारों में से छह उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इस प्रकार यह कमी सिर्फ राजनीतिक दलों से ही नहीं, बल्कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में भी देखने को मिलती है। 2014 के चुनावों में, 33 स्वतंत्र महिला प्रतियोगी थीं , जिनकी इस बार संख्या केवल 25 हैं। ऐसे भी कई निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां यह एक ऑल–मेन शो रहा है। 2014 में, शून्य महिला उम्मीदवारों के साथ 23 निर्वाचन क्षेत्र थे। इस बार 32 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां कोई महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल द्वारा कई प्रमुख महिलाओं को मैदान में उतारा गया हैं। इंडियन नेशनल लोकदल (प्छस्व) ने 15 महिलाओं को मैदान में उतारा है, भाजपा ने 12, कांग्रेस ने 9 और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने 7 उम्मीदवार उतारे हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव की रौनक– 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 21 अक्टूबर को हुआ। जिसमें पहलवान बबीता फोगट (दादरी), टीवी अभिनेत्री सोनाली फोगट (आदमपुर) और लंदन लौटे नौशाम चौधरी (पुन्हाना) भाजपा के युवा चेहरों में से हैं। सोनाली को पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मैदान में उतारा गया। भजनलाल परिवार 1967 से कभी भी आदमपुर से विधानसभा चुनाव नहीं हारे। खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में तीन बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री, कविता जैन को सोनीपत से फिर से मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी और मौजूदा विधायक प्रेम लता उचाना कलां से फिर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी (तोशाम) और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल को मैदान में उतारा।

चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने एक महिला प्रदेश अध्यक्ष – कुमारी शैलजा को भी नियुक्त किया गया। चौटाला परिवार के 'बहू' नैना चौटाला को जेजेपी द्वारा बड़हरा से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे रणबीर महिंद्रा के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। जेजेपी के साढौरा के उम्मीदवार, कुसुम शेरवाल ने 2014 में अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ा था। नारनौल से मैदान में उतारे गए कमलेश सैनी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन लगभग 4,000 मतों से हार गए थे। इनेलो ने 33 फीसदी महिला उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी। "हमारे 86 उम्मीदवारों में से 15 महिलाएँ हैं। हमने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पूरी कोशिश की। "इनेलो महासचिव आर

एस चौधरी ने कहा। स्वराज इंडिया, जिसने यह भी कहा था कि वह 33 प्रतिशत महिलाओं को मैदान में लाएगी, उसके 28 प्रतियोगियों में पाँच महिलाएँ हैं। स्वराज इंडिया के हरियाणा अध्यक्ष राजीव गोदारा ने कहा कि वे हरियाणा में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण महिलाओं के लिए एक तिहाई टिकट सुनिश्चित नहीं कर सके।

निष्कर्ष– हालाकि, भारत जैसे देश में जहाँ महिलाएँ लगभग आधी आबादी का निर्माण करती हैं, परंतु सत्ता में उनका प्रतिनिधित्व कम ही रहा है जिसका एक कारण पितृसत्ता और रूढ़िवादी मानसिकता है। बबिता फोगाट जैसी नव उम्मीदावाद को लोगो द्वारा इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा कयोंकि वह उम्र में राजनीति के ज्ञान में बहुत कम है दूसरा वह एक लड़की है। ऐसी समस्याओं के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दहिया के एक प्रोफेसर ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को चुनावी राजनीति में मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा चुना जाना चाहिए। जब महिलाओं में 50 फीसदी आबादी होती है, तो उन्हें आधे टिकट क्यों नहीं दिए जाते? उन्होने कहा "2016 के पंचायत चुनावों में, 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, लेकिन उन्होंने लगभग 45 प्रतिशत सीटें जीतीं। इसका मतलब है कि वे जीतने में सक्षम हैं। महिलाओं को सिर्फ रैलियां में उपस्थिति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, "दहिया ने कहा, जो बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान के लिए कुरुक्षेत्र जिला ब्रांड एम्बेसडर हैं।

वहीं दूसरी ओर महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों की तुलना में हरियाणा में अधिक सक्रिय हैं, चाहे वह खेतों में हो या पशुधन के लिए प्रवृत्त हो, उन्होंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि छह महिला उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, न कि अपने राजनीतिक कारण के लिए, बल्कि अपने परिजनों के कारण। इसके साथ ही हरियाणा के गरीब हिस्सों की महिलाओं को चुनाव के वादों में कोई दिलचस्पी नहीं है भविष्य के लिए उनकी अपनी स्वयं की ही योजनाएं हैं।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

# विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281